Publication Division, which remained unsold during the last five years; and

(b) what is the total loss to the State exchequer on this account?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) In the last five years, Publications Division brought out 456 books with a total print order of 22.5 lakhs. Out of this, 71 books having a total print order of 10.66 lakhs have been fully sold out. The remaining 385 titles are still being sold. The Division brought out 21 periodicals with a print order of 880 lakhs approximately which were distributed and sold.

(b) Some of the books published during the last five years are live titles and are still selling. The periodicals are meant to serve publicity purposes. The Publications Division is a publicity oriented department and normal commercial norms of profitability etc. do not apply to them.

खाद्यान्न का नुकसान

481. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन और भण्डारण के दौरान भारतीय खाद्य निगम में हर साल खाद्यान्नों की बरबादी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना खाद्यान्न बरबाद हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने निगम के घाटों में हो रही वृद्धि को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम के समग्र आर्थिक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करने को कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को हुई खाद्यान्नों की मार्गस्थ और भण्डारण हानियां निम्नानुसार हैं :

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	खरीद-बिक्री	हानि	खरीद-बिक्री के प्रति हानि की प्रतिशतता
1984-85	295.14	5.72	1.94
1985-86	368.40	5.95	1.62
1986-87	398.96	6.51	1.63

(ग) और (घ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों की लागत लेखापरीक्षा करने के लिए कहा गया है। इस बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता

482. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई वर्षों से भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों पर दी गई राजसहायता लगातार बढ़ाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी राजसहायता दी गई ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उचित दर की दुकानों पर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य पिछले कई वर्षों के दौरान बढ़ा दिए गए हैं ; यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान वस्तुओं के मूल्यों में वर्षवार कितनी-कितनी बार वृद्धि की गई और उक्त अवधि के दौरान हर साल अप्रैल मास में गेहूं का विक्रय मूल्य क्या था ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम को 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान दी गई सबसिडी की राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपये (करोड़ में)
1985-86	1650
1986-87	2000
1987-88	2000

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में की गई वृद्धि इस प्रकार है :—

गेहूं	(रुपये प्रति क्विंटल)
को निर्गम मूल्य	
1-4-1985	172.00
1-2-1986	190.00
1-5-1987	195.00
25-3-1988	204.00

चावल	साधारण	बढ़िया	उत्तम
को निर्गम मूल्य			
1-4-1985	208.00	220.00	235.00
10-10-1985	217.00	229.00	244.00
1-2-1986	231.00	243.00	253.00
1-10-1986	239.00	251.00	266.00
1-10-1987	239.00	264.00	279.00